



# रोजगार समाचार



साप्ताहिक

खण्ड 38 अंक 35 पृष्ठ 72

नई दिल्ली 30 नवंबर - 6 दिसंबर 2013

₹ 8.00

अतुल्य पूर्वोत्तर!

## पूर्वोत्तर भारत के लिए बुनियादी ढांचे का समावेशी विकास

एस एन ब्रह्मो चौधरी और सोनल ढींगरा

यह व्यापक आम सहमति है कि बुनियादी ढांचे का विकास और वृद्धि में योगदान रहता है। यह उत्पादकता में सुधार, निजी पूंजी के स्थायित्व में वृद्धि और स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक परिणामों में स्पष्ट रूप से दीर्घावधि सुधार लाने में भी मददगार होता है। लेकिन बुनियादी ढांचा प्रबंधन में कमी, अनियमित राजस्व प्रवाह और लंबी परिपक्वता अवधियों के कारण संभावित निवेश में व्यापक कमी हो जाती है। अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता सीमित होती है और मुख्यतः वार्षिक बजटीय सहायता पर निर्भर करती है। बुनियादी ढांचा सृजन के लिए कोष संबंधी केंद्रीय और राज्य सरकारों की क्षमता समय-समय पर काफी भिन्न हो सकती है।

पूर्वोत्तर भारत में राज्यों के लिए संपर्क सुविधा सबसे बड़ी विकास चुनौती है, जिसके कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच परस्पर कमजोर संपर्क है। इन छोटे राज्यों की संसाधन सृजन क्षमता बहुत अधिक नहीं है और स्थापना लागत में अवसंरचना विकास के लिए कुछ न कुछ गुंजाइश बनी रहती है। इन राज्यों को संसाधन सृजन क्षमता के अधिकतम उपयोग के वास्ते अपने प्रयासों को सुदृढ़ करना चाहिए। सामान्यतः यह माना जाता है कि जब तक भौतिक अवसंरचना का सृजन नहीं कर दिया जाता और संपर्क स्थापित नहीं हो जाता, 'पूर्व की ओर देखो' नीति को पूर्णरूपेण हासिल नहीं करना कठिन बना रहेगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के विकासात्मक कार्य स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछेक भू-

भौतिकीय एवं ऐतिहासिक कठिनाइयों को न्यूनतम करते हुए राज्य योजनाओं के अधीन केंद्रीय सहायता से पूरे किये जाते हैं। 1996 में 'पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नई पहलें' पर प्रमुख नीतिगत घोषणा में कई उपाय शामिल किये गये थे, जिनमें प्रमुख क्षेत्रों में विशेष क्षेत्र विकास परियोजनाएं सम्मिलित हैं। इसके परिणामों में केंद्रीय मंत्रालयों के योजना बजट का 10 प्रतिशत का निर्धारण करना और चिह्नित निधि से नॉन-लैप्सेबल पूल का सृजन करना शामिल है। दरअसल नौवीं योजना के बाद के हिस्से में ही प्रमुख क्षेत्रों में अवसंरचना की कमी की पहचान के लिए कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं को प्राथमिकता मिली। इसके साथ-साथ मानव संसाधन और कौशल में निवेश भी विकास के लिए प्रमुख केंद्र बिंदु बन गया था।

केंद्रीय और स्थानीय सरकार की तरफ से किये गये सतत प्रयासों और स्थानीय पणधारियों के साथ संपर्कों से क्षेत्र में धीरे-धीरे कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार आया है। इससे 10वीं योजना अवधि के दौरान परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मदद मिली है। सर्वोच्च स्तर पर नियमित निगरानी प्रणाली ने कुछेक योजना विनिर्दिष्ट समस्याओं जैसे कि भूमि अधिग्रहण, वन्य स्वीकृति आदि के समाधान के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। 10वीं और 11वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन निगरानी के साथ राज्य योजनाओं को केंद्रीय सहायता में व्यापक इजाजत से स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास में मदद मिली है। इससे राज्यों में आर्थिक गतिविधियां सृजित हुईं जो इनके विकास में स्पष्ट झलकती हैं।

नौवीं योजना में विकास दर 5.3 प्रतिशत से सुधरकर 10वीं योजना में 6.2 प्रतिशत हो गई। 11वीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में औसत सकल घरेलू उत्पाद की दर 8.0 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 9.8 प्रतिशत थी। यहां तक कि यदि सिक्किम की विशिष्ट वृद्धि दर (22 प्रतिशत) को अलग भी कर दिया जाए तो पूर्वोत्तर क्षेत्र की औसत दर पूर्ववर्ती

योजनाओं से काफी ऊपर (7.9 प्रतिशत) है। 12वीं योजना में केंद्रीय क्षेत्र की वर्तमान में जारी परियोजनाओं (सड़कें, रेल, हवाई अड्डा, दूरसंचार और विद्युत) को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों ने प्रमुख संपर्क और विद्युत परियोजनाओं की धीमी प्रगति के बारे में चिंताएं व्यक्त की हैं जो कि व्यापार और वाणिज्य के लिए व्यापक क्षमताएं होने के बावजूद निजी निवेश को प्रभावित कर रही हैं। उत्तर पूर्व औद्योगिक नीति एनईआईपी के तहत विशेष वित्तीय पैकेज से यथा अपेक्षित बहुत अधिक निवेश प्रवाह सुनिश्चित नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में निजी निवेश का हिस्सा, लेटर ऑफइन्टेंट डाटा पर आधारित, 0.6 प्रतिशत से कम है।

प्रधानमंत्री ने 18 जुलाई, 2013 को पूर्वोत्तर क्षेत्र में भौतिक अवसंरचना के उन्नयन के लिए संचालित की जा रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इसके बाद सभी संबंधित मंत्रालयों ने नियमित समीक्षाएं की हैं। इन समीक्षाओं के दौरान यह बात सामने आई कि कुछेक परियोजनाएं लगभग पूरा होने वाली हैं लेकिन कुछ परियोजनाओं में स्थल चयन, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय और वन्य स्वीकृति, धन की कमी, सुरक्षा संबंध मुद्दों आदि की समस्याओं के कारण देरी हुई है। अतः सरकार ने तीन महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं, (1) हारमुति-नाहरलागुन (अरुणाचल प्रदेश), (2) दुधनोई मेंडिपटार (मेघालय), (3) रंगपापड़ा-नार्थ लखीमपुर (असम) को मार्च, 2014 से पहले पूरा करने का काम तेजी करने का फैसला किया है। यदि अपेक्षित हुआ तो महत्वपूर्ण परियोजनाओं अर्थात् (क) लुमडिंग-सिल्वर (ख) बोगिबील ब्रिज को निर्धारित सीमा में पूरा करने के लिए (क्रमशः जून, 2015 और मार्च, 2016 में) अतिरिक्त संसाधन भी उपलब्ध कराए जायेंगे।

प्रमुख सड़क कार्यक्रमों के लिए, जैसे कि पूर्व पश्चिम कोरीडोर, पूर्वोत्तर के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (फेस-क), जिला कनेक्टिविटी के

साथ ट्रांस अरुणाचल हाईवे आदि के लिए जमीन पर सड़क निष्पादन सक्षमताओं को सुदृढ़ीकरण से वर्तमान परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन पर फोकस किया जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिणी किनारे पर राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ते हुए धोला-साडिया पुल का काम तेज किया जा रहा है जिससे प्रमुख रूप से अरुणाचल प्रदेश के दिबांग, पासीघाट, रोइंग क्षेत्रों को फायदा पहुंचेगा। साथ ही साथ मणिपुर में जिरिबाम-इम्फाल (एनएच-53), त्रिपुरा में एनएच-44, मिजोरम में लांगतलाई से म्यांमार सीमा (एसएआरडीपी-एनई-फेस क का हिस्सा) तक नियमित रूप से मानीटरिंग की जा रही है। म्यांमार और बंगलादेश के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र को पहुंच बढ़ाने के वास्ते ये महत्वपूर्ण संपर्क है।

विद्युत क्षेत्र में, दो महत्वपूर्ण ताप विद्युत परियोजनाएं, अर्थात् पलटाना (726 मेगावाट) और बोंगईगांव (750 मेगावाट) हैं जो लगभग पूरी होने वाली हैं। पारेषण लाइनों के साथ-साथ ये परियोजनाएं विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई हैं, जिनसे कुछ हद तक विद्युत की उपलब्धता में सुधार होगा। लोअर सुबानसिरि (2000 मेगावाट) परियोजना कार्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई हैं ताकि इसका काम शीघ्रतापूर्वक चालू किया जा सके। इन मुद्दों का इस वर्ष के अंत तक समाधान कर लिये जाने के प्रयास जारी हैं। इस परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र में विद्युत की कमी को व्यापक रूप से दूर किया जा सकेगा।

विस्तारित अवसंरचना निवेशों से उत्पादकता में सुधार और संपूर्ण आर्थिक विकास से बहुत अधिक महत्वपूर्ण फायदे होंगे। आने वाले समय में, इससे वार्षिक विकास दर बढ़ेगी और राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान होगा।

(एसएन ब्रह्मो चौधरी योजना आयोग में सलाहकार हैं और सोनल ढींगरा योजना आयोग, नई दिल्ली में एक युवा विशेषज्ञ हैं)

### महत्वपूर्ण सूचना

#### नई दरें

एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापनों के लिए डीएवीपी दरें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार के 7 दिसंबर 2013 के अंक से संशोधित करके ₹ 190.44 प्रति वर्ग सें.मी. कर दी गई हैं। सभी विज्ञापनदाताओं से अनुरोध है कि वे इसे नोट कर लें और तदनुसार भुगतान करें।

### रोजगार सारांश

#### रेलवे

- पश्चिमी रेलवे, मुंबई को 5775 गैंगमैन/ट्रैकमैन, हैल्पर, खलासी आदि की आवश्यकता।

अंतिम तिथि: 14.01.2014

#### बैंक

- जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक, जम्मू को 248 अधिकारी स्केल-1 और कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय) की आवश्यकता।

अंतिम तिथि: 12.12.2013

- प्रथमा बैंक, मुगदाबाद को 138 अधिकारी स्केल-III, अधिकारी स्केल-II, अधिकारी स्केल-I और कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय) की आवश्यकता।

अंतिम तिथि: 11.12.2013

#### क.च.आ

- कर्मचारी चयन आयोग, पश्चिमी क्षेत्र को 195 सहायक पादप संरक्षण अधिकारी, अन्वेषक और डाटा एंट्री आपरेटर ग्रेड 'बी' की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 27.12.2013

### वेब विशेष

www.rojgarsamachar.gov.in के वेब विशेष खण्ड में निम्नलिखित आलेख उपलब्ध हैं:

1. भारतीय महिला बैंक (बीएमसी)

## मेकाट्रॉनिकी के क्षेत्र में कैरिअर

मेकाट्रॉनिकी यांत्रिक इंजीनियरी के वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक के बारे में होती है। सामान्य शब्दों में यह इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा नियंत्रित यांत्रिक प्रणालियों के निर्माण से संबंधित है। मेकाट्रॉनिकी प्रासंगिक रूप में इंजीनियरी की एक नई शाखा है, जो कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से स्वीकार की जा रही है। यह वैद्युत इंजीनियरी इलेक्ट्रॉनिकी, यांत्रिक एवं कम्प्यूटर विज्ञान इंजीनियरी का एक अंतरविषयीय विज्ञान है। मेकाट्रॉनिकी का उद्देश्य अभिन्न प्रणालियों को सरल, उपयोग के लिए आसान, लागत प्रभावी तथा विश्वसनीय प्रणालियां बनाना है।

औद्योगिक रोबोटिक्स मेकाट्रॉनिकी प्रणाली एक शानदार उदाहरण है। वास्तव में मेकाट्रॉनिकी का अनुप्रयोग विभिन्न उपकरणों के आंतरिक कार्य पर मोबाइल फोन से लेकर वाशिंग मशीनों, रासायनिक संयंत्र मशीनरी, पॉवर जेनरेटर, ऑटो-फोकस कैमरा एवं रोबोट पर प्रदर्शित होता है।

### मेकाट्रॉनिकी का अनुप्रयोग

मेकाट्रॉनिकी इंजीनियर बड़ी हुई कार्य क्षमता के साथ

हाइब्रिड प्रणालियों-यांत्रिक प्रणालियों के डिजाइन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे अपने ज्ञान का यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिकी, कम्प्यूटर विज्ञान में प्रयोग करते हैं और विभिन्न उद्योगों के उत्पादों, प्रोसेस तथा सेवाओं को सुधारने के लिए सिद्धांत को नियंत्रित करते हैं।

### मेकाट्रॉनिक इंजीनियर

- औद्योगिक कार्यों के स्वचलन के लिए स्मार्ट उपकरणों एवं अभिन्न प्रणालियों का डिजाइन एवं विकास कार्य करते हैं।
- औद्योगिक स्वचलन में अनुसंधान करते हैं और चुनौतियों का समाधान खोजते हैं।
- औद्योगिक विनिर्माण प्रोसेस का रखरखाव एवं सुधार कार्य करते हैं।
- कुशल एवं लागत प्रभावी मेकाट्रॉनिक उपकरणों के प्रोटोटाइप का निर्माण करते हैं।
- प्रयोक्ता अनुभव बढ़ाने पर लक्षित वीडियो रिकॉर्डर जैसे उपभोक्ता उत्पादों का डिजाइन तथा विनिर्माण कार्य करते हैं।
- खनन जैसे खतरनाक कार्यों में मानवीय

हस्तक्षेप को हटाने के लिए उपकरण प्रोसेस कार्य करते हैं।

- संभाव्यता अध्ययन करते हैं और बजट की योजना बनाते हैं।
  - सुरक्षा प्रक्रिया की रूप रेखा बनाते हैं।
  - अपने कार्य का प्रलेखन करते हैं।
- इंजीनियरी क्षेत्रों के अपूर्व सहयोग से रोबोटिक्स, जैसे नए अंतरविषयीय क्षेत्र उभर रहे हैं। उद्योग अपनी प्रैक्टिस तथा पद्धतियों के अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी उन्नति ला रहे हैं। सीमित संसाधनों से परियोजना कार्यान्वयन की आवश्यकता बढ़ रही है। इसलिए, मेकाट्रॉनिकी को इस क्षेत्र में स्थापित होना ही है।

मेकाट्रॉनिकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरी, जैव-चिकित्सा इंस्ट्रुमेंटेशन, औद्योगिक स्वचलन, रोबोटिक्स, एवियोनिक्स, डाटा संचार नेटवर्क, एम्बेडेड तथा रियल टाइम प्रणालियों, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, मानव-मशीन इंटरफेस इंजीनियरी एवं मोशन नियंत्रण आदि जैसे अनेक क्षेत्रों में जहां

(शेष पृष्ठ 72 पर)

## मेकाट्रॉनिकी के क्षेत्र...

(पृष्ठ 1 का शेष)

यांत्रिक उपकरणों के इलेक्ट्रॉनिक कार्य- निष्पादन को बढ़ाया जाना है, अनुप्रयोग में लाई जाती है। मेकाट्रॉनिकी प्रणालियों की समर्थक एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो प्रोसेस संयंत्रों के रिसाव (लीक) तथा खराबियों पर निगरानी रखती है। एंटी-लॉक ब्रेक इसी प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। फ्लाइट सिमुलेटर भी मेकाट्रॉनिकी इंजीनियरी की देन हैं।

### अध्ययन विकल्प:

मेकाट्रॉनिकी यांत्रिकी, वैद्युत, इलेक्ट्रॉनिकी, जैव-चिकित्सा, संचार, इंस्ट्रूमेंटेशन, औद्योगिक, विनिर्माण, उत्पादन, आंतरिक तथा रासायनिक इंजीनियरी जैसी शैक्षिक पृष्ठ भूमि वाले उम्मीदवारों के लिए खुली है।

मेकाट्रॉनिकी एक शैक्षिक विकल्प है जो डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उपलब्ध है। डिप्लोमा स्तर का पाठ्यक्रम इंजीनियरी पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को मेकाट्रॉनिकी के मूल सिद्धांतों (बेसिक्स) को सीखने तथा उसे उनके कार्यों में लागू करने में, सहायता करता है। स्नातक डिग्री मेकाट्रॉनिकी के क्षेत्र में कॅरिअर प्रारंभ करने के लिए अपेक्षित संकल्पनाओं तथा सिद्धांतों को मजबूत आधार देती है। एम.टेक. कार्यक्रम यह जानकारी देता है कि मेकाट्रॉनिकी को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे अनुप्रयुक्त किया जाता है। पाठ्यक्रम में ऑटोमोबाइल तथा वाहन इंटेलेक्जेंस, रोबोट डायनामिक्स तथा विश्लेषण, फज्जी लॉजिक एवं न्यूरल नेटवर्क, मेकाट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन एवं डिजिटल नियंत्रण प्रणालियां जैसे विषय शामिल हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मेकाट्रॉनिकी एक अनुप्रयोग विज्ञान भी है, आप इस विषय को स्नातकोत्तर स्तर पर भी चुन सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिकी या यांत्रिक इंजीनियरी जैसे मुख्य इंजीनियरी विषय में बी.टेक. के बाद में लिया जा सकता है। इस तरह, आप डायनामिक प्रणालियों सहित अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और मेकाट्रॉनिकी के प्रभाव को अच्छी तरह समझ सकते हैं।

### अपेक्षित कौशल

मेकाट्रॉनिकी के क्षेत्र में अपना कॅरिअर प्रारंभ करने के लिए आपको व्यापक तकनीकी कौशल प्राप्त करना होगा। भौतिकी, डिजिटल प्रणाली डिजाइन, मेकाट्रॉनिकी मॉडलिंग, इलेक्ट्रो-मेगनेटिक्स, विनिर्माण, प्रोसेस, निर्णय लेने के सिद्धांतों एवं सर्किट विश्लेषण का उत्कृष्ट ज्ञान होना अनिवार्य है।

मेकाट्रॉनिकी के क्षेत्र में कार्यों में, विविध विषय सीमा में चुनौतियों का सामना करने के लिए, यांत्रिक इंजीनियरों तथा सॉफ्टवेयर विकासकर्ता जैसे अन्य क्षेत्रों के व्यवसायियों से सहयोग करना शामिल है। इसलिए अच्छा संचार कौशल होना आवश्यक है। एकजुट होकर कार्य करने, विविध कार्य करने, कार्य-तनाव सहने, नई सोच तथा समस्या का समाधान करने की क्षमता जैसे कौशल होना भी आवश्यक है।

### कार्य:

मेकाट्रॉनिकी इंजीनियर प्रोसेस संयंत्रों, इंजीनियरी डिजाइन कार्यालयों, प्रयोगशालाओं तथा कारखाने जैसे स्थानों पर कार्य करते हैं। वे क्षेत्र, जहां मेकाट्रॉनिकी इंजीनियर रोजगार तलाश सकते हैं। वे हैं- रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल, जैव इंजीनियरी, नेनोटेक्नॉलोजी, एयरोस्पेस, उपभोक्ता उत्पाद, एम्बेडेड सिस्टम, विनिर्माण, खनन, वानिकी, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार। अनुसंधान संगठन तथा शैक्षिक संस्थाएं भी मेकाट्रॉनिकी इंजीनियरी को रोजगार पर रखते हैं।

कालेज तथा पाठ्यक्रम				
पाठ्यक्रम	कॉलेज	पात्रता	प्रवेश	वेबसाइट
मेकाट्रॉनिकी में एम.टेक.	वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, वेल्लोर	यांत्रिक इंजीनियरी, वैद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार इंजी;	प्रवेश परीक्षा/ गेट में प्रदर्शन	www.vit.ac.in
		ऑटोमोबाइल इंजीनियरी, कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजी. में स्नातक डिग्री में 50% अंक		
मेकाट्रॉनिकी में एम.टेक	एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा	यांत्रिक/इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार या वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी में बी.ई./बी.टेक/ए.एम.आई.ई. तथा 60% अंक एवं+2 स्तर पर न्यूनतम 60% अंक	प्रवेश परीक्षा/ गेट में प्रदर्शन	www.amity.edu
मेकाट्रॉनिकी में एम. टेक	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर	यांत्रिक इंजी., वैद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिकी इंजी., इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार इंजी., ऑटोमोबाइल इंजीनियरी, उत्पादन इंजी., कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी में स्नातक डिग्री.	प्रवेश परीक्षा/ गेट में प्रदर्शन	www.iiitdmj.ac.in
मेकाट्रॉनिकी में एम. टेक	बंगाल इंजीनियरी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर, पश्चिम बंगाल	यांत्रिक/मेकाट्रॉनिकी/उत्पादन/ऑटोमोबाइल/विनिर्माण/वैमानिक/वैद्युत/इलेक्ट्रॉनिकी/दूरसंचार/इंस्ट्रूमेंटेशन/नियंत्रण इंजी. में बी.ई./बी.टेक में 60% अंक	प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन	www.becs.ac.in
बी.टेक मेकाट्रॉनिकी इंजीनियरी	एस.आर.एम. विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	गणित, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान विषयों के रूप में लेकर 10+2	प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन	www.srmuniv.ac.in
बी.टेक मेकाट्रॉनिकी	विज्ञान विश्व-विद्यालय, आंध्र प्रदेश	गणित, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान विषयों के रूप में लेकर 10+2	प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन	www.vignanuniversity.org
मेकाट्रॉनिकी में डिप्लोमा	जीडी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (जी.टी.टी.आई.) कोयम्बतूर	एस.एस.एल.सी./मैट्रिकुलेशन/एच.एस.सी.	प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन	www.gttiinfo.com
मेकाट्रॉनिकी इंजीनियरी में डिप्लोमा	के.एम.जी. पॉलिटैकनीक, तमिलनाडु	दसवीं कक्षा/एस.एस.सी./मैट्रिक/के.मा.शि.बो./एंग्लो	शैक्षिक रिकॉर्ड	www.kmgpolytechnic.com

(यह लेख TMIE2E अकादमी कॅरिअर केन्द्र, सिकंदराबाद (आं.प्र.)द्वारा दिया गया है। ई-मेल: [faqs@tmie2e.com](mailto:faqs@tmie2e.com))

## पूर्वोत्तर राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए तत्पर

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए तैयारी के पुनरीक्षण हेतु गुवाहाटी में हाल में, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के खाद्य मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गयी। लक्ष्मि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) यथा अतिरिक्त भण्डारण सुविधा उत्पन्न करने, खाद्यान्न की घर-घर तक सुपुर्दगी, टीपीडीएस का कम्प्यूटरीकरण का पूर्वोत्तर राज्यों में भूभाग, अभिगम्यता, खाद्यान्न का परिवहन, भण्डारण सुविधाएं इत्यादि की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विस्तार से चर्चा की गयी। बैठक की अध्यक्षता प्रो. केवी थॉमस उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के केन्द्रीय मंत्री और असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा के खाद्य मंत्री उपस्थित हुए। इनके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के प्रधान सचिव/खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के प्रभारी सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया। राज्य ने मार्च 2014 अथवा अधिनियम 2014 के मध्य तक इसके कार्यान्वयन के संकेत दिए।

प्रो. थॉमस ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन सभी राज्यों के खाद्यान्नों का आबंटन न केवल विद्यमान टीपीडीएस के अधीन बीपीएल और एएवाई घरेलू के लिए वर्तमान में प्राप्त राज्यों से अधिक होगा अपितु गेहूं/चावल के लिए 2/3 प्रति किलोग्राम की उच्चतर सहायता पर होगा, जबकि बीपीएल आबंटन का जारी मूल्य कहीं अधिक है। संगत विकास के संदर्भ में, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निर्बाध कार्यान्वयन के लिए, गुवाहाटी में एक प्रशासनिक एकक स्थापित कर रहा है। अभी पूर्वोत्तर में 468000 मी.टन की क्षमता के साथ 77 एफसीआई डिपो परिचालन में हैं। इसके अलावा वर्तमान में 20 परियोजनाएं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा में निर्माणाधीन हैं जो लगभग 125060 मी.टन की भण्डारण क्षमता की अभिवृद्धि करेंगी जिसमें से 53000 मी.टन मार्च 2014 तक पूर्ण होने की संभावना है।

## कृपया ध्यान दें

पहली दिसम्बर, 2013 से रोजगार समाचार/(हिन्दी अथवा उर्दू) एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ (अंग्रेजी) की ई-संस्करण सुविधा, केवल व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी।

## सूचना

रोजगार समाचार में छपे लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जरूरी नहीं है कि वही विचार सरकार के या जिन संगठनों के लिए लेखक कार्य करते हैं, उनके हों। रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु संगठन या उनके प्रतिनिधियों की है। रोजगार समाचार इन विज्ञापनों की विषयवस्तु/पाठ के कारण उत्पन्न होने वाले किसी विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है।

## निःशक्त छात्रों हेतु 2000 छात्रवृत्तियां

- तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु छात्रवृत्तियां
- स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु
- प्रवेश शुल्क, शिक्षा शुल्क, रखरखाव भत्ते तथा छात्रावास शुल्क शामिल
- दोनों प्रकार की छात्रवृत्तियां हेतु आय सीमा रु. 3 लाख/1.80 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए
- हमारी वेबसाइट [www.nhfdc.nic.in](http://www.nhfdc.nic.in) देखें



निःशक्तजनों का सशक्तिकरण

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन  
(निःशक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

रेड क्रॉस भवन, सैक्टर-12, फरीदाबाद-121007  
दूरभाष : 0129-2287512, 0129-2287513, फैक्स : 0129-2284371  
ई-मेल : [nhfdc97@gmail.com](mailto:nhfdc97@gmail.com), वेबसाइट : [www.nhfdc.nic.in](http://www.nhfdc.nic.in) रो. स. 35/71

## रोजगार समाचार

निधि पांडे  
निदेशक, महाप्रबंधक एवं मुख्य संपादक  
डॉ. ममता रानी  
संपादक  
नलिनी रानी  
संपादक (विज्ञापन एवं संपादकीय)  
इरशाद अली (संपादक वितरण)  
आफ़ाक़ अहमद एहसानि  
संपादक  
विनोद कुमार मीणा  
संयुक्त निदेशक (उत्पादन)  
पी.के. मंडल  
वरिष्ठ कलाकार  
केपी मणिलाल  
लेखा अधिकारी

संपादकीय कार्यालय  
रोजगार समाचार  
पूर्वी खण्ड IV तल-5, रामकृष्णपुरम  
नई दिल्ली-110066  
ई-मेल-संपादकीय : [enewsedit@gmail.com](mailto:enewsedit@gmail.com)  
विज्ञापन : [enewsadvt@yahoo.com](mailto:enewsadvt@yahoo.com)  
संपादकीय : 26163055  
विज्ञापन : 26104284  
टेलीफैक्स : 26193012  
वितरण : 26107405  
टेलीफैक्स : 26175516  
प्रोडक्शन : 26177529  
लेखा (विज्ञापन) : 26193179  
लेखा (वितरण) : 26182079